नईदुनिया

भोपाल, 11 नवंबर 2026

खास-खबरें

राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 6.0 के लिए आवेदन आमंत्रित

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: डीपीआईआईटी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के छठे संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत विजेताओं को हर श्रेणी में को 25 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। डीपीआईआईटी ने 'एक्स' पर जारी पोस्ट में बताया कि इसके तहत देशभर के ऐसे स्टार्टअप्स को मान्यता दी जाएगी जो इनोवेटिव (नवाचारी) हैं, जिन्हें बड़े स्तर पर बढ़ाया जा सकता है और जिनका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 6.0 के लिए आवेदन 27 अक्टूबर से 20 नवंबर, 2026 तक खुले हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार इन पुरस्कारों के जरिये नवोन्मेषण, विस्तार क्षमता, टिकाऊ विकास और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप की पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य कृषि से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक 20 विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्यमों की पहचान करना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करना है।

डीजीटीआर ने चीन, मलेशिया और वियतनाम से एल्युमीनियम उत्पादों की डंपिंग की शुरू की जांच

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली:। वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने चीन, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड से एल्यूमीनियम उत्पादों की कथित डंपिंग के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की है। डीजीटीआर की अधिसूचना के अनुसार भारत इन देशों से होने वाले सस्ते आयात से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की इकाइयों को बचाना चाहता है। डीजीटीआर की 9 नवंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक उसे एल्युमीनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एलेमाई) से अभ्यावेदन मिले हैं। यह संगठन 'एल्युमीनियम एक्सट्रूजन प्रोफाइल, स्ट्रक्चर और उत्पादों' के 228 विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है। महानिदेशालय ने कहा कि डंपिंग के जरिये आयात में उल्लेखनीय वृद्धि से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। आमतौर पर, घरेलू उत्पादकों की ओर से आवेदन दाखिल किए जाने के आधार पर डीजीटीआर डंपिंग-रोधी जांच को शुरू करता है। हालांकि, उद्योगों के पास अक्सर व्यापार उपचार जांच के लिए जरूरी जानकारी एवं विशेषज्ञता नहीं होती है। ऐसे में निदेशालय स्वत: पहल कर इन मामलों की जांच करता है।

कच्चे तेल की कीमत में गिरावट जारी, 90 डॉलर के स्तर से भी नीचे आया ब्रेंट क्रूड

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट में जियो पॉलिटिकल टेंशन कम होने की उम्मीदों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। सोमवार को कच्चे तेल के भाव तीन महीने के निचले स्तर पर फिसल गए थे। इसके बाद आज भी कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का रुख बना हुआ है। इस बड़ी गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ताजा बयान को माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया है कि ईरान पर अब और नए हमले की आवश्यकता नहीं होगी। इस गिरावट के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत अब 90 डॉलर प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर से भी नीचे पहुंच गई है।

भारतीय समय के अनुसार दोपहर एक बजे के करीब ब्रेंट क्रूड पिछले बंद भाव 92.57 डॉलर के मुकाबले 3.39 डॉलर यानी 3.66 प्रतिशत गिर कर 89.18 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक चला गया था। हालांकि बाद में इसकी स्थिति में मामूली सुधार भी हुआ। फिलहाल, शाम 4:15 बजे ब्रेंट क्रूड 2.69 डॉलर यानी 2.91 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करते हुए 89.88 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

इसी तरह अमेरिकी क्रूड यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) के भाव में भी भारी फिसलन देखी जा रही है। डब्ल्यूटीआई क्रूड आज अपने पिछले बंद भाव 86.85 डॉलर के मुकाबले 2.97 डॉलर यानी 3.42 प्रतिशत की गिरावट का शिकार होकर 83.88 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि बाद में इसकी चाल में थोड़ी तेजी आई, जिसके कारण शाम 4:15 बजे डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.95 डॉलर प्रति बैरल यानी 2.25 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 84.90 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था। कच्चे तेल के इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो अक्टूबर के अंत में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 6 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंची हुई थीं।

चीनी महिला से संबंधों के विवाद के बीच जेन्सन हुआंग को आर्थिक झटका

फोर्ब्स की अमीरों की सूची में एक स्थान नीचे खिसके संपत्ति घटकर 14.32 लाख करोड़ रुपये हुई

वाशिंगटन, एजेंसी: एनवीडिया के प्रमुख जेन्सन हुआंग की संपत्ति में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फोर्ब्स की अमीरों की सूची में वे एक स्थान नीचे खिसककर 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनकी कुल संपत्ति 6.80 अरब डॉलर घटकर 155.4 अरब डॉलर रह गई है। भारतीय मुद्रा में यह गिरावट करीब 63 हजार करोड़ रुपये है और उनकी संपत्ति घटकर लगभग 14.32 लाख करोड़ रुपये रह गई है।

इस गिरावट की प्रमुख वजह एनवीडिया के शेयरों में आई बिकवाली बताई गई है। कंपनी का शेयर 4.27 प्रतिशत गिरकर 178.67 डॉलर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसमें आठ प्रतिशत से अधिक की गिरावट भी दर्ज की गई थी। हालांकि, बाद में शेयर में कुछ सुधार हुआ। हुआंग की संपत्ति का बड़ा हिस्सा एनवीडिया में उनकी हिस्सेदारी से जुड़ा है। उनके पास कंपनी के 3.5 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं और वे इसके सबसे





बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक हैं।

चीनी महिला से संबंधों को लेकर विवाद

हुआंग का नाम चीनी महिला एलिस हुआंग के साथ कथित संबंधों को लेकर चर्चा में है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि एलिस चीन की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही थीं। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, हुआंग ने रविवार को कंपनी के कर्मचारियों को भेजे संदेश में अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई स्वीकार की। उन्होंने लिखा कि उनके इस कदम से पत्नी और बच्चों को गहरा दुख पहुंचा है और उन्हें इसका पछतावा है। उन्होंने भरोसा बनाए रखने में विफल रहने पर भी खेद जताया। हालांकि, संदेश में एलिस का नाम नहीं लिया गया।

कौन हैं एलिस हुआंग

एलिस चीन की नागरिक हैं और सिंगापुर की आंकड़ा केंद्र से जुड़ी कंपनी मेगास्पीड में वरिष्ठ अधिकारी रह चुकी हैं। प्रौद्योगिकी और आंकड़ा केंद्र क्षेत्र में आने से पहले वह दूरदर्शन पत्रकार थीं। दोनों की साथ मौजूदगी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जून 2024 में ताइपे के एक बार में दोनों अन्य प्रौद्योगिकी अधिकारियों के साथ दिखाई दिए थे। मई 2025 में भी एक रात्रिभोज के बाद एलिस को हुआंग के पीछे खड़े देखा गया था। इन घटनाओं और आरोपों के बीच हुआंग की व्यक्तिगत संपत्ति में आई गिरावट ने भी ध्यान खींचा है।

त्यौहार के चलते आज शेयर बाजार में कारोबार नहीं

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: बलिप्रतिपदा के अवसर पर मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में कारोबार बंद रहा। हालांकि, बहुवस्तु वायदा बाजार में शाम पांच बजे से रात 11:30 बजे तक कारोबार होगा। वहीं, राष्ट्रीय कृषि एवं व्युत्पन्न बाजार पूरे दिन बंद रहेगा। इस दौरान एशियाई और अमेरिकी बाजारों में तेजी दर्ज की गई। पिछले कारोबारी दिन नौ नवंबर को सेंसेक्स 107 अंक की बढ़त के साथ 81,107 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 58 अंक चढ़कर 25,045 के स्तर पर पहुंच गया था। उस दिन सरकारी बैंक और औषधि कंपनियों के शेयरों में खरीदारी रही, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी और धातु कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखी गई। विदेशी बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 4.08 प्रतिशत चढ़कर 5,235 पर पहुंच गया। जापान का निक्केई 2.65 प्रतिशत बढ़कर 60,476 पर और हांगकांग का हैंगसेंग 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,491 पर रहा। अमेरिकी बाजार भी पिछले कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए। डाउ जोंस में 2.15 प्रतिशत, नैस्डैक में 2.74 प्रतिशत और एसएंडपी 500 में 2.35 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले सात दिनों में भारतीय बाजार में 43,221 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इसी अवधि में 27,998 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की। वर्ष 2026 में राष्ट्रीय शेयर बाजार और मुंबई शेयर बाजार के लिए कुल 16 कारोबारी छुट्टियां निर्धारित की गई हैं।

दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर लग सकता है शुल्क

ग्राहक पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त बोझ; नई व्यवस्था लागू होने की तारीख तय नहीं

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: त्योहारों का मौसम समाप्त होने के बाद अब एक बार फिर एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के नए शुल्क को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत दो हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर दुकानदारों को 0.4 प्रतिशत व्यापारी छूट दर (एमडीआर) शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि, इसे लागू करने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पहले इस व्यवस्था को 15 अक्टूबर से लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन त्योहारों के दौरान बढ़ते कारोबार और डिजिटल भुगतान को देखते हुए इसे टाल दिया गया था। निगम ने कहा था कि नई व्यवस्था दीपावली के तुरंत बाद लागू की जाएगी।



कितना देना पड़ सकता है शुल्क

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, दो हजार 500 रुपये के भुगतान पर दुकानदार को 10 रुपये, पांच हजार रुपये पर 20 रुपये और 10 हजार रुपये पर 40 रुपये शुल्क देना पड़ सकता है। वहीं, 75 हजार रुपये या इससे अधिक के भुगतान पर अधिकतम 300 रुपये ही शुल्क लगेगा। यह राशि दुकानदार के खाते से काटी जाएगी। ग्राहक को इसके लिए अलग से भुगतान नहीं करना होगा।

कारोबारियों ने किया था विरोध

इस प्रस्ताव का देशभर के कारोबारी संगठनों और विपक्षी नेताओं ने विरोध किया था। कारोबारियों का कहना था कि इससे छोटे व्यापारियों की लागत बढ़ेगी और उनके मुनाफे पर असर पड़ेगा। उनका यह भी मानना था कि त्योहारों के दौरान नई व्यवस्था लागू करने से भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी आशंका को देखते हुए दीपावली तक शुल्क लगाने का फैसला टाल दिया गया था। अब त्योहार समाप्त होने के बाद प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने की तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है।

प्रस्तावित शुल्क की तीन प्रमुख बातें

प्रस्ताव के अनुसार, यदि ग्राहक दुकानदार को दो हजार रुपये से अधिक का भुगतान करता है तो कुल राशि पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगेगा। हालांकि, 75 हजार रुपये या उससे अधिक के बड़े भुगतान पर प्रतिशत के बजाय अधिकतम 300 रुपये का निश्चित शुल्क निर्धारित किया गया है। रेलवे, दूरसंचार, बीमा और ईंधन से जुड़े दो हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर प्रति लेनदेन पांच रुपये का निश्चित शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।

डायसन ने भारत में उतारे दो नए पंखे, एक सर्दी में देगा गर्म हवा तो दूसरा करेगा ठंडक का एहसास

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी डायसन ने भारत में दो नए पंखे पेश किए हैं। इनमें से एक उपकरण सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के साथ गर्मियों में ठंडी हवा भी देगा। वहीं, दूसरा केवल ठंडी हवा देने के लिए तैयार किया गया है। दोनों उपकरणों में कंपनी की एयर मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इनका डिजाइन सामान्य पंखों से अलग है और इनमें बाहर की ओर घूमने वाले पंखे नहीं दिखाई देते।

कंपनी के हॉट-कूल एचएफ1 रिमोट लिंक प्री-हीट की कीमत 38,900 रुपये रखी गई है। इसमें सिरेमिक हीटिंग प्लेटें लगी हैं। कंपनी का दावा है कि यह लगभग 100 सेकंड में कमरे का तापमान एक डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है। इसमें तापमान संवेदक और थर्मोस्टेट दिया गया है। उपयोगकर्ता अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान निर्धारित कर सकते हैं। उपकरण कमरे के तापमान के अनुसार गर्मी को नियंत्रित करता है।

इसमें हवा की गति के लिए 10 विकल्प और 70 डिग्री तक घूमने की सुविधा है। इसे मोबाइल अनुप्रयोग और दूरस्थ नियंत्रण यंत्र से संचालित किया जा सकता है। पहले से कमरा गर्म करने की सुविधा भी दी गई है। इसमें रात्रि विधा और समय निर्धारित करने का विकल्प मौजूद है। कंपनी के अनुसार, यह पिछले प्रारूप की तुलना में 25 प्रतिशत कम आवाज करता है। गिरने पर अपने आप बंद होने की सुरक्षा सुविधा भी है। दूसरे उपकरण डायसन कूल टावर पंखे की कीमत 27,900 रुपये है। इसमें 10 गति विकल्प, दूरस्थ नियंत्रण और समय निर्धारण की सुविधा है। यह केवल ठंडी हवा देता है, कमरे का तापमान कम नहीं करता। दोनों उपकरण वायु शोधक नहीं हैं और इनमें प्रदूषक कणों को हटाने वाला छन्ना नहीं दिया गया है।

सोनिया गांधी की नई पुस्तक ब्लिंकिट पर 849 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' क्विक कॉमर्स मंच ब्लिंकिट पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। ब्लिंकिट पर उपलब्ध उत्पादों की सूची के मुताबिक इस मंच पर यह पुस्तक 849 रुपये में उपलब्ध है। हार्डकवर में प्रकाशित इस किताब का मुद्रित मूल्य 1,299 रुपये है। इस तरह यह करीब 35 फीसदी छूट पर उपलब्ध है। ब्लिंकिट के मुकाबले ई-कॉमर्स मंच अमेजन पर इस पुस्तक की डिलिवरी में 48 घंटे तक का समय लगने का अनुमान जताया गया है।

कम बजट में 5जी स्मार्टफोन खरीदने का मौका

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कम कीमत में आधुनिक सुविधाओं वाला स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए बाजार में कई विकल्प उपलब्ध हैं। 15 हजार रुपये से कम कीमत वाली श्रेणी में ऐसे पांच स्मार्टफोन चर्चा में हैं, जिनमें तेज गति वाली स्क्रीन, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 6000 एमएएच तक की बैटरी जैसी सुविधाएं मिलती हैं। आजकल स्मार्टफोन खरीदते समय ग्राहक केवल कैमरे और बैटरी की क्षमता ही नहीं देखते, बल्कि उसकी कार्यक्षमता और गति पर भी ध्यान देते हैं। मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला चिपसेट इसकी कार्यक्षमता का महत्वपूर्ण आधार होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े कई कार्यों का प्रदर्शन भी चिपसेट की क्षमता पर निर्भर करता है। इस मूल्य श्रेणी के कई स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा दिया जा रहा है। इससे अच्छी रोशनी में स्पष्ट तस्वीरें लेने में मदद मिलती है। वहीं, 6000 एमएएच क्षमता वाली बैटरी लंबे समय तक उपयोग की सुविधा देती है। ऐसे मोबाइल उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जो दिनभर फोन का इस्तेमाल करते हैं। कई कम कीमत वाले स्मार्टफोन में उच्च आवृत्ति वाली स्क्रीन दी जा रही है। इससे मोबाइल पर तस्वीरें देखने, खेल खेलने और इंटरनेट चलाने का अनुभव अधिक सहज होता है।

पानी में भी चलेगी बीवाईडी की नई इलेक्ट्रिक कार, टैंक की तरह ले सकेगी मोड़

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: चीन की वाहन निर्माता कंपनी बीवाईडी ने अपनी नई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार यांगवांग ऑल्टियर पेश की है। इस कार की सबसे खास बात इसकी विशेष तकनीक है, जिसकी मदद से यह पानी में तैरने के साथ टैंक की तरह अपनी जगह पर घूम सकती है। इसके बाहरी डिजाइन में ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस की गाड़ियों जैसी झलक दिखाई देती है।

कंपनी ने इस वाहन को अत्याधुनिक सुविधाओं और विशेष तकनीकी क्षमताओं के साथ प्रदर्शित किया है। इसकी बनावट को प्रीमियम श्रेणी के ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कार का आकर्षक बाहरी स्वरूप इसे सामान्य इलेक्ट्रिक वाहनों से अलग पहचान देता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में पानी में तैरने की क्षमता शामिल है। यह तकनीक वाहन को विशेष परिस्थितियों में पानी के ऊपर बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा इसमें ऐसा घुमाव तंत्र दिया गया है, जिससे कार बिना सामान्य मोड़ लिए अपनी जगह पर घूम सकती है। यह सुविधा संकरी जगहों पर वाहन को मोड़ने और नियंत्रित करने में उपयोगी हो सकती है।

टैंक की तरह घूमने वाली तकनीक वाहन के पहियों को अलग-अलग दिशा में नियंत्रित करने की क्षमता पर आधारित होती है।

मशरूम की खेती बनी आत्मनिर्भरता का जरिया, महिलाएँ कर रहीं अच्छी कमाई

- प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं से छोटे प्रयासों को मिल रही उद्यम की पहचान
- कई गांव बने मशरूम उत्पादन के केंद्र

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश में स्वास्थ्यवर्धक भोजन की बढ़ती मांग के बीच मशरूम की खेती किसानों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए आजीविका का नया साधन बन रही है। कम जमीन, पानी और पूंजी में इसकी खेती संभव है। इसमें कृषि अपशिष्ट का उपयोग होने से लागत भी अपेक्षाकृत कम रहती है। मशरूम प्रोटीन, रेशे, विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत हैं। सरकार प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग के माध्यम से इस खेती को प्रोत्साहित कर रही है।

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के



इप्पटम गांव की 20 वर्षीय रुथु इसका उदाहरण हैं। पहले कचरा बीनकर आजीविका चलाने वाली रुथु ने ग्रामीण युवाओं के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। कृषि विज्ञान केंद्र, गुंटूर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने दूधिया मशरूम की खेती शुरू की। उनका उत्पादन प्रतिदिन लगभग आठ किलोग्राम तक पहुंच गया, जिससे उन्हें करीब 35 हजार रुपये मासिक आय होने लगी। उनके प्रयास से गांव के अन्य लोगों ने भी यह खेती शुरू की। बिहार के नालंदा जिले के अनंतपुर गांव की अनीता देवी ने भी मशरूम उत्पादन को सामुदायिक उद्यम का रूप दिया। वर्ष 2010 में कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत से जुड़ने के बाद उन्होंने ऑयस्टर और मिल्की व्हाइट मशरूम की खेती शुरू की। उनके प्रयासों से आसपास की महिलाएं भी इससे जुड़ने लगीं। वर्ष 2012 में कृषि विभाग ने अनंतपुर को मशरूम ग्राम घोषित किया। अनीता ने 15 लाख रुपये की सरकारी सहायता से मशरूम बीज उत्पादन प्रयोगशाला स्थापित की। वर्ष 2023 तक नालंदा में जीविका स्वयं सहायता समूहों की 250 से अधिक महिलाएं मशरूम आधारित आजीविका से जुड़ चुकी थीं।

गुजरात के तापी जिले की सिविल अभियंता अंजनाबेन गामित ने वर्ष 2017 में प्रशिक्षण लेकर ऑयस्टर मशरूम की खेती शुरू की। शुरुआती ढाई महीने में उन्हें 140 किलोग्राम उत्पादन से 28 हजार रुपये की आय हुई। वर्ष 2019 में उत्पादन केंद्र का विस्तार करने के बाद उन्होंने अप्रैल से दिसंबर के बीच 1,234 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन किया। इससे उन्हें लागत घटाने के बाद 2.20 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।

उत्तराखंड के देहरादून जिले के चरबा गांव की हिरेशा वर्मा ने वर्ष 2013 में केवल 25 थैलों और दो हजार रुपये के निवेश से मशरूम की खेती शुरू की। शुरुआती सफलता के बाद उन्होंने इसे व्यावसायिक उद्यम में बदल दिया। ये उदाहरण बताते हैं कि प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण मशरूम बीज और बाजार तक पहुंच मिलने से मशरूम की खेती ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

स्पेशल खबर लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में टूना मछली...

समुद्री संसाधनों से रोजगार और निर्यात बढ़ाने की तैयारी

- समुद्री शैवाल और सजावटी मछलियों के उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश की नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करने के लिए सरकार लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही है। इन क्षेत्रों में टूना मछली, समुद्री शैवाल और सजावटी मछलियों के उत्पादन तथा प्रसंस्करण की व्यापक संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए 218 करोड़ और लक्षद्वीप के लिए 175 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया गया है।



देश के पास लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा और करीब 24 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। यहां समुद्री मत्स्य पालन की अनुमानित क्षमता 58.6 लाख मीट्रिक टन है। यह क्षेत्र करीब 50 लाख मछुआरों की आजीविका से जुड़ा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात लगभग 73,890 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2015 से सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र में 39,272 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।

लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा समेटे हुए हैं। दोनों क्षेत्रों में टूना मछली की विभिन्न प्रजातियों की उपलब्धता के कारण गहरे समुद्र में मत्स्य पालन की बड़ी संभावनाएं हैं। सरकार आधुनिक मछली पकड़ने वाले जहाजों, शीत भंडारण, प्रसंस्करण और निर्यात सुविधाओं के विकास पर जोर दे रही है।

लक्षद्वीप में पांच वर्षीय योजना के तहत टूना उत्पादन दोगुना कर 50 हजार टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों और पारंपरिक पर्यावरण अनुकूल तरीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में समर्पित टूना समूह के माध्यम से जहाजों के आधुनिकीकरण और शीत भंडारण क्षमता बढ़ाने की योजना है।

इसके अलावा समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मछली पालन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लक्षद्वीप में 300 से अधिक प्रजातियों की सजावटी मछलियां पाई जाती हैं। समुद्री शैवाल का उपयोग खाद्य पदार्थों, औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों और अन्य औद्योगिक उत्पादों में होता है। सरकार मछली उतारने के केंद्रों, बर्फ निर्माण संयंत्रों, शीत भंडारण, नौका निर्माण और प्रसंस्करण इकाइयों का विकास भी कर रही है। इन प्रयासों से स्थानीय रोजगार, मछुआरों की आय और समुद्री खाद्य निर्यात बढ़ाने के साथ समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण करने पर जोर दिया जा रहा है।

पीएफ खाते में गलत जानकारी से अटक सकता है आपका पैसा, घर बैठे सुधारें विवरण

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि खाते में नाम, जन्मतिथि, लिंग या अन्य व्यक्तिगत जानकारी गलत दर्ज होने पर खाताधारकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी गलतियों के कारण भविष्य निधि की राशि निकालने, दावे के निपटारे और खाते का हस्तांतरण करने में अड़चन आ सकती है। इस समस्या से बचने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाताधारकों को ऑनलाइन संयुक्त घोषणा सुविधा के माध्यम से विवरण सुधारने की जानकारी दी है। इस सुविधा की मदद से कर्मचारी घर बैठे अपने खाते में दर्ज गलत जानकारियों को ठीक करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले संगठन के आधिकारिक जालस्थल पर जाकर सार्वभौमिक खाता संख्या और कूटशब्द की सहायता से प्रवेश करना होगा। इसके बाद संयुक्त घोषणा सुविधा का विकल्प चुनना होगा।

दस्तावेजों से मेल खाना चाहिए विवरण

संगठन के अनुसार, सुधार के लिए दी गई जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों का आपस में मेल होना जरूरी है। अनुरोध जमा होने के बाद उसे सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर संबंधित जानकारी आधिकारिक अभिलेखों में संशोधित कर दी जाएगी। संयुक्त घोषणा कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से दी जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से भविष्य निधि खाते में व्यक्तिगत और रोजगार संबंधी जानकारियों में सुधार किया जाता है। पहले इसके लिए कागजी प्रपत्र भरकर भविष्य निधि कार्यालय जाना पड़ता था, लेकिन अब सदस्य जालस्थल के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। खाताधारकों को अपनी सार्वभौमिक खाता संख्या को आधार से जोड़कर रखना चाहिए। दोनों में नाम की वर्तनी समान होनी चाहिए।

पांच चरणों में सुधारें जानकारी

- सबसे पहले भविष्य निधि संगठन के सदस्य जालस्थल पर प्रवेश करें।
- संयुक्त घोषणा सुविधा के विकल्प पर जाएं।
- जिस जानकारी में सुधार करना है, उसका चयन करें और सही विवरण दर्ज करें।
- सुधार के समर्थन में आधार कार्ड, स्थायी खाता संख्या या जन्म प्रमाणपत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- सभी जानकारियों और दस्तावेजों की जांच करने के बाद अनुरोध जमा कर दें।